...रज आनंद लिखार, चीफ सिटी प्लानर, नगर निगम.

16 यूनिवर्सिटी, 528 कॉलेजों में तैयार होगा ई-ग्रंथालय, 11 मेंबर्स की टीम करेगी निगरानी

प्लेटफॉर्म डेवलप कर किताबों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

प्रदेश में भोपाल की बरकतउल्ला सहित 16 यूनिवर्सिटी और 528 कॉलेजों में ई-ग्रंथालय (ई-लायब्रेरी) बनाया जाएगा। जहां ई-लायब्रेरी को लेकर काम हुआ है, वहां इसका अपग्रेडेशन होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 11 मेंबर्स की स्टेट लेवल की टीम बना दी है। इस टीम का काम ई-ग्रंथालय से जुड़े कामों की मॉनीटरिंग करना होगा।

ई-ग्रंथालय के तहत दो तरह के काम किए जा रहे हैं। इनमें इसके सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट के अलावा ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना भी है जिसमें किताबों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके बाद छात्र इसका उपयोग कर सकें, इसके लिए उन्हें लिंक और पासवर्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वे कहीं से भी इसका एक्सेस कर सकें। सॉफ्टवेयर से संबंधित काम एनआईसी को दिया गया है जबकि कौन सी किताबें अपलोड की जानी है और किस तरह के अपग्रेडेशन होना चाहिए, इसका काम स्टेट लेवल टीम के जिम्मे होगा।

स्टूडेंट्स कहीं से भी इसका एक्सेस कर सकेंगे

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-ग्रंथालय में कोर्स बुक्स के अलावा रिसर्च पेपर को भी शामिल किया जा रहा है। स्टूडेंट्स इसका एक्सेस कर सकेंगे। इस व्यवस्था में वे किताब को अपलोड भी कर सकते हैं। इससे उनका खर्च भी बचेगा। कहीं से भी इसका एक्सेस संभव हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल ऑफिसर डॉ. सुनील कुमार सिंह को बनाया गया है। इसमें तीन ओएसडी और सीनियर लायब्रेरियन भी शामिल रहेंगे।

कोर्स की किताबें और रिसर्च पेपर उपलब्ध होंगे

छात्रों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत कोर्स की किताबें, रिसर्च पेपर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए संबंधित कॉलेज उन्हें एप या अन्य तरह से लिंक और पासवर्ड देंगे। इसके बाद छात्र किताबों को अपलोड कर सकेंगे। इससे लाखों छात्रों को लाभ होगा।

– दीपक सिंह, आयुक्त ,उच्च शिक्षा

Date: Dainink Jagran, Bhopal City Ed. 20/04/2022

प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एनआइसी के सॉफ्टवेयर का होगा इस्तेमाल

ई-लाइब्रेरी क्रांति लाने वाले सोल सॉफ्टवेयर से मोह भंग, अब ई-ग्रंथालय पर आया दिल

पत्रिका एक्सक्लूसिव

श्याम सिंह तोमर
patrika.com

भोपाल. उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों में यूजीसी के जिस आधुनिक लाइब्रेरी मैनजेमेंट सॉफ्टवेयर (सोल) के मार्फत ई-लाइब्रेरी क्रांति की, अब आला अफसर उसे धराशायी करने में जुट गए हैं। जिम्मेदारों ने 13 अप्रेल को सरकारी 529 कॉलेजों के प्राचार्यों के नाम पत्र जारी किया कि अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए एनआइसी के ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉलेजों को औसतन 25 हजार रुपए खर्च कर पांच साल के लिए सॉफ्टवेयर मिलेगा। 2003 से अब तक 350 कॉलेजों की लाइब्रेरी का ऑटोमेशन और रिसर्च डाटाबेस तैयार करने के काम पर करोड़ों (प्रति संस्थान करीब एक लाख रुपए के हिसाब से) खर्च किए जा चुके हैं। यूजीसी के इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर (इनफ्लिबनेट) के सोल सॉफ्टवेयर से राज्य के कॉलेजों को ई-बुक्स व ई-जर्नल्स की सुविधा भी मिल रही है, जो अब छिनती दिखाई दे रही है।

किया था एमओयू

उच्च शिक्षा विभाग ने 2003 में कॉलेजों में लाइब्रेरी ऑटोमेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। यूजीसी के इनफ्लिबनेट जिसके जिम्मे देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की लाइब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण और रिसर्च डाटाबेस तैयार करने यानी ई-लाइब्रेरी बनाने का काम था, उसे शुरू किया गया। पहले चरण में 80 सरकारी कॉलेजों के लिए विभाग और यूजीसी के इनफ्लिबनेट के बीच एमओयू हुआ। विभाग ने अनुदान दिया ताकि कॉलेज सॉफ्टवेयर खरीदी और ऑटोमेशन कर सकें। इस बीच अभी तक 350 कॉलेजों के परंपरागत ग्रंथालय ई-लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं।

25 हजार रुपए खर्च प्रति कॉलेज आएगा

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के ओएसडी डॉ. सुनील सिंह के अनुसार सोल सॉफ्टवेयर कितने कॉलेजों में लागू है, इसकी जानकारी नहीं... लेकिन ई-ग्रंथालय पर प्रति कॉलेज 25 हजार रुपए खर्च आएगा। (पुराने सॉफ्टवेयर पर हर कॉलेज ने औसत एक लाख रुपए खर्च किया था, अब इसे लागू करने के पीछे क्या वजह है, इस पर बोले...) देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तकनीकी रूप से मुझे ज्यादा नहीं पता।

इससे पहले हजारों रुपए हुए खर्च

एनआइसी के नए सॉफ्टवेयर को लेने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के पदेन स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्ट और आयुक्त उच्च शिक्षा दीपक सिंह ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया है। ऐसे में पूर्व में सोल सॉफ्टवेयर जिसके कॉलेज वर्जन पर औसत हर संस्थान ने 50 हजार रुपए तो नेटवर्क वर्जन बड़े संस्थानों ने लिए था, उस पर औसत 75 हजार रुपए खर्च किए थे।

Dainik Jagran, 22/04/2022